खोरी में 'आप' और बीएसपी की नौटंकी, किसान आंदोलनकारी भी कूदे

कहीं से ठोस आश्वासन अभी तक यहां रहने वाले बाशिंदों को नहीं मिला

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: अरावली जोन में बसे खोरी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने 22 जून को यहां राजनीतिक नाटक खेला। इस नाटक के चक्कर में पार्टी में दरार पड़ गई और कई इस्तीफे हो गए। इसके बाद बीएसपी भी इस मैदान में कूदी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक ट्वीट करके उजाड़ने से पहले बसाने की अपील की है। उधर, आंदोलनकारी किसान भी खोरी की जनता के साथ खड़े हो गए हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 30 जून को यहां महापंचायत बुलाई है। खोरी को लेकर किसान नेताओं के तेवर कड़े हैं। इस बीच आधा से ज्यादा खोरी का इलाका खाली हो चुका है। लोगों ने अपने सामान रिश्तेदारों या किराये के मकानों में दिल्ली-फरीदाबाद में पहुंचा दिया है और अब सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

मुझे गिरफ्तार तो कर लो कम से कम : सराय ख्वाजा में न तो खोरी की जनता पहुंची और न आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन सुशील गुप्ता गिरफ्तारी देने जा पहुंचे।

खोरी के बहाने राजनीतिक जमीन तलाशती आप

खोरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी अपनी ही राजनीति खेल रही है। हालांकि वो राजनीति अब उन्हें बैकफायर कर गई है। खोरी को लेकर आप के जिला अध्यक्ष धर्मवीर भड़ाना और बडखल विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष तेजवंत सिंह बिट्टू और उनकी टीम पहले से ही आंदोलन कर रही थी। खोरी को जब राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज मिलने लगा तो अचानक हरियाणा के आप प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को भी इस आंदोलन में कूदने की जरूरत महसूस होने लगी। उन्होंने 22 जून को खोरी के लोगों के साथ प्रधानमंत्री निवास घेरने की घोषणा कर दी। ऐसी घोषणाओं का क्या मतलब और मकसद होता है, यह पुलिस और राजनीतिक दलों से छिपा नहीं है। इसी बीच 21 जून को खोरी के लोगों से मिलने पहुंचे तेजवंत सिंह बिट्टू, जोगेन्द्र चावला, हरजिंदर सिंह, परमजीत कौर, एडवोकेट डी.एस. चावला और मनोज और उनकी टीम के लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके फरीदाबाद पुलिस को सौंप दिया। इन पर खोरी के लोगों को उकसाने का आरोप लगाया गया। ये लोग जैसे-तैसे छूट तो गए लेकिन इन्हें बहुत बुरा अनुभव किया कि पार्टी के राज्यसभा सांसद और हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता उन लोगों के साथ नहीं खड़े हुए और न एक बार पुलिस थाने इन लोगों को छुड़ाने पहुंचे। 22 जून को तेजवंत बिट्टू और उनकी टीम ने स्वास्थ्य कारणों का बहाना लेकर पार्टी छोड़ दी और घर बैठ गए। जमीनी कार्यकर्ताओं के घर बैठने पर सुशील गुप्ता को होश आया लेकिन वो 22 जून के आंदोलन का ऐलान कर चुके थे।

22 जून को सुशील गुप्ता सराय ख्वाजा पहुंचे और वहां खोरी के लोगों का इंतजार करने लगे, ताकि दिल्ली कूच किया जा सके। लेकिन वहां खोरी से कोई नहीं पहुंचा। सुशील गुप्ता ने धर्मवीर भड़ाना के जरिए मीडिया को बुलाया और पुलिस वालों के सामने कहा कि पुलिस खोरी के लोगों को पीएम निवास कूच करने के लिए सरायख्वाजा आने नहीं दे रही है, इसलिए वे गिरफ्तारी दे रहे हैं। सुशील गुप्ता के इस बयान पर साइड में खड़े पुलिस वाले भी हंसते रहे। खैर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की औपचारिकता पूरी की। कुछ देर बाद धर्मवीर भड़ाना को सूरजकुंड पुलिस ने गिरफ्तार करने की रस्म अदा की।

बाद में शाम को सुशील गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें सारा दिन फरीदाबाद के विभिन्न थानों में घुमाती रही। गुप्ता ने यह भी दावा किया कि शाम को प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाकर खोरी के लोगों की तरफ से ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिसमें पुनर्वास की मांग की गई है।

उधर, धर्मवीर भड़ाना से तेजवंत सिंह बिट्टू के इस्तीफे के बारे में गुरुवार को बात की गई तो भड़ाना ने कहा कि बिट्टू कहीं नहीं जाएगा, वो शुक्रवार या शनिवार तक पार्टी में लौट आएगा। भड़ाना ने पार्टी में टूट की बात स्वीकार नहीं की लेकिन वो इस बात का मतलब भी नहीं समझा सके कि जो नेता स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देकर गया हो, वो इतनी जल्दी कैसे वापस आ सकता है। लेकिन वो यही कहते रहे कि बिट्टू जी पार्टी में आ जाएंगे।

आम आदमी पार्टी हरियाणा में प्रभारी सुशील गुप्ता के रवैए को लेकर पहले से ही रोष है। सोनीपत के बुटाना में दलित लड़की से पुलिस चौकी के अंदर 10-12 पुलिस वालों ने गैंगरेप किया। सोनीपत के आप कार्यकर्ता सुशील गुप्ता को बुलाते रहे, लेकिन यह शख्स वहां नहीं पहुंचा। नतीजा यह निकला कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे पर चल रहे आंदोलन से पीछे हटना पड़ा। जबकि कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे थे कि आप इस मुद्दे पर राज्यस्तरीय आंदोलन खड़ा कर सकती है। बहरहाल, हरियाणा के हर जिले में राज्य प्रभारी सुशील गुप्ता के ढीले-ढाले रवैए को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह हमारी समझ से बाहर है कि भाजपा को लेकर हमारा प्रभारी इतना ढीला क्यों रहता है।

बसपा भी तलाश रही कुछ

बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को खोरी के मुद्दे पर ट्वीट करके हलचल पैदा करने की कोशिश की। मायावती ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि सरकार खोरी के लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास का इंतजाम करे। मायावती ने लिखा है - जनहित, जनसुरक्षा व जनकल्याण को संवैधानिक दायित्व स्वीकारते हुए हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के खोरी गाँव में वर्षों से बसे लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बीएसपी की यह सलाह व माँग। हालांकि इसी मुद्दे पर मायावती से भी पहले भीम आर्मी के अध्यक्ष चन्द्रशेखर रावण ने कहा था - सरकार दिल्ली-फरीदाबाद की सीमा पर बसे खोरी गांव में हजारों घरों को हटाने के फिराक में है। लोगों की जिंदगी खतरे में है। इस महामारी में वे कहां जाएंगे ? पुनर्वास के बगैर विस्थापन मंजूर नहीं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विपदा की इस घड़ी में हम खोरी की जनता के साथ हैं।

चन्द्रशेखर एक बयान के बाद चुप हो गए लेकिन बीएसपी सक्रिय हो गई। बीएसपी के जिला फरीदाबाद अध्यक्ष मनोज यादव खोरी में हालात का जायजा लेकर आए। बीएसपी ने खोरी में रहने वाले मुस्लिमों से संपर्क साधा है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि अभी तो हम आशियाने की तलाश में हैं। अभी बसपा-सपा के चक्कर में पड़ने का समय नहीं है। यानी बसपा जिस कैडर की तलाश में खोरी में है, उसे मिल नहीं रहा है।

किसान नेताओं ने की आवाज बुलंद

खोरी के लोगों ने कुंडली बॉर्डर पर जाकर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी व अन्य नेताओं से मुलाकात की। चढ़ूनी ने कहा कि हम लोग खोरी को नहीं उजड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सरकार उन्हें उजाड़ती है तो खोरी वालों को भी कुंडली बॉर्डर पर लाकर बसा देंगे। चढ़ूनी ने खोरी गांव में 30 जून को पंचायत बुलाने का एलान किया। उन्होंने पूरे हरियाणा और देश की जनता से खोरी गांव के लोगों का साथ देने की भी अपील की। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "क्या खोरी गांव की उसी जमीन पर जंगल बनाना जरूरी है जहां पिछले कई दशकों से लोग रह रहे हैं, क्या खाली पड़ी जमीनों पर जंगल नहीं बनाए जा सकते, जब कॉलोनी काटी जा रही थी, लोग अपने मकान बना रहे थे तब सरकार और प्रशासन कहां था।"

चढ़ूनी ने कहा, "जहां लोग रह रहे हैं उनको वहां से उजाड़कर उसी जगह पर पेड़ लगाना कौन-सा कानून है। सरकार को हमारी चेतावनी है कि इन लोगों को वहां से न हटाया जाए। अगर हटाना है तो सरकार पहले इन लोगों को दूसरी जगह मकान बनाकर दिए जाएं वरना इन परिवारों को हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर खोरी गांव के लोगों के साथ छेड़छाड़ की गई तो इन एक लाख लोगों को भी कुंडली बॉर्डर जारी किसानों के धरने पर लेकर आएंगे। कुंडली बॉर्डर पर ही इन लोगों की खाने-पीने और रहने की व्यवस्था होगी और खोरी गांव के लाखों लोग भी हमारे साथ धरने में शामिल होंगे।

बीस दिन हो चुके फैसला आए

खोरी से अतिक्रमण हटाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए अभी तक 20 दिन हो चुके हैं लेकिन इलाके में पुलिस तैनात करने के अलावा और कोई नया घटनाक्रम सरकारी तौर पर सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने पिछले हफ्ते खोरी के लोगों का पुनर्वास करने का संकेत दिया था, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसीएफ और जिला प्रशासन को खोरी से अतिक्रमण हटाने का डेढ़ महीने का समय दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारी हरियाणा सरकार की ओर से फाइनल झंडी का इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर इन लोगों के पुनर्वास का वादा करके और समय मांग सकती है। लेकिन यहां भी राजनीति है। पहले तो भाजपा नेताओं ने गोदी मीडिया में खबरें छपवाईं कि यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है और यहां अपराधी रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरों पर यूपी-बिहार के यहां रह रहे लोगों ने आपत्ति जताई तो भाजपा नेता बैकफुट पर आ गए। फिलहाल खोरी में बीजेपी नेताओं की घुसने की हिम्मत नहीं हो रही हैं जबकि लॉकडाउन के दौरान इस इलाके में क्षेत्रीय भाजपा विधायक सीमा मास्क और सेनेटाइजर बांटती घूम रही थीं।

कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति

एमसीएफ ने खोरी के मामले में अपने किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। जबकि एमसीएफ के अफसरों का खोरी में अवैध निर्माण कराने में बहुत बड़ा हाथ है। अभी भी एमसीएफ के कुछ एसडीओ और जेई जो खोरी के मामले में बदनाम है। वे अच्छी सीटों पर टिके हुए हैं और एनआईटी में अवैध निर्माण कराने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एमसीएफ ने खानापूर्ति के नाम पर प्रोपर्टी डीलर अनंगपाल के अलावा 20 अज्ञात भूमाफिया के खिलाफ नगर निगम फरीदाबाद ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।

देखी-सुनी

खबरीलाल

भाजपा के दावे और फिर फजीहत

हरियाणा भाजपा की गुरुवार को कार्यकारिणी बैठक थी। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने आंकड़ा पेश किया कि 30 मई को मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर हरियाणा भाजपा इकाई ने 6 लाख मास्क और सेनिटाइजर बांटे, 21,000 राशन किट बांटे, 47,000 केयर किट बांटे, 1.88 लाख थर्मल स्कैनर बांटे और 600 स्थानों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाया। इस बयान के सामने आते ही हरियाणा के लोगों ने सोशल मीडिया पर भाजपा वालों से तीखे सवाल पूछना शुरू कर दिए। मंजीत कुमावत ने लिखा- ये सब दे तो रहे हैं लेकिन क्या पता इसका कई गुणा हम ही लोगों से भाजपा वाले वसूल लें। हमें इस तरह की हमदर्दी नहीं चाहिए। पेट्रोल, डीजल के दाम कम करो, महंगाई घटाओ तब मानेंगे कि भाजपा कुछ कर रही है। खुद को आरएसएस कार्यकर्ता बताने वाले गौरव ने लिखा-हरियाणा की आबादी ढाई करोड़ और मास्क बांटे बस 6 लाख। पूनम चौधरी ने लिखा-ये भाजपा वाले रोजाना झूठ बोलते हैं। एक अन्य ने लिखा - राम मंदिर का चंदा क्या इसीलिए लूटा था। इस सबके बावजूद मनोज यादव को रणछोड़ दास बनने की अपेक्षा भ्रष्टाचारियों एवं साम्प्रदायिक तत्वों से डरकर लोहा लेना चाहिये था। उनसे निपटने के लिये अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिये था। उसके बाद यदि सरकार चाहती खूद उनकी विदाई का प्रयास करती।

क्यों भाग रहे हैं डीजीपी मनोज यादव

हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव वापस केंद्र में आईबी में जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की गुड बुक्स में होने के बावजूद आखिर मनोज इस पावरफुल पोस्ट को क्यों छोड़ना चाहते हैं। सरकार पर नजदीक से नजर रखने वालों का कहना है कि मनोज यादव के खिलाफ अफसरों की पूरी लॉबी जुट गई है। अकेले वाई. पूर्णकुमार का मामला ही नहीं है, जिस पर वो नाराज हैं। दरअसल, डीजीपी कुछ जिलों में भ्रष्ट किस्म के पुलिस अफसरों को हटाना चाहते हैं। लेकिन वही भ्रष्ट पुलिस अफसरों ने संघ और भाजपा के नेताओं से संपर्क साध कर उल्टा मनोज यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में एक सीनियर आईपीएस अफसर ने आरएसएस हरियाणा के पदाधिकारियों को समझाया है कि इस डीजीपी के रहते हम लोग स्वयंसेवक की तरह संघ के लिए कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए इस लॉबी ने पुलिस थानों में मंदिर वाली बात का मुद्दा भी उठाया। मनोज यादव ने अपने एक पत्र में सभी पुलिस थानों से पूजा स्थल हटाने को कहा था। आमतौर पर हरियाणा के बहुत सारे पुलिस थानों और चौकियों में मंदिर ही बने हुए हैं। मनोज यादव की इस पहल को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। एक और वजह ये भी है कि गृह मंत्री अनिल विज से डीजीपी की पट भी नहीं रही है। उन्हें एक्सटेंशन देने का विज ने विरोध किया था। बताया जाता है कि हाल ही में विज ने केंद्रीय नेताओं के सामने भी हरियाणा के डीजीपी का मुद्दा रखा था।

इस सबके बावजूद मनोज यादव को रणछोड़ दास बनने की अपेक्षा भ्रष्टाचारियों एवं साम्प्रदायिक तत्वों से डटकर लोहा लेना चाहिये था। उनसे निपटने के लिये अपनी वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिये था। उसके बाद यदि सरकार चाहती तो खूद उनकी विदाई का प्रयास करती।

मंदिर बनाने का पुलिसिया धंधा

मंदिर बनाने का पुलिसिया धंधा साम्प्रदायिकता व अंधविश्वास फ़ैलाने के साथ-साथ कमाई का भी एक साधन होता है। मंदिर बनाने के नाम पर थाने-चौकी में आने वाले लोगों से मंदिर के नाम पर किसी से ईंट किसी से सिमेंट तो किसी से लोहा लक्कड़ आदि की मांग की जाती है। अपना काम निकलवाने की मजबूरी में आगंतुक बजाए बजार से समान ढोकर लाने को इसकी कीमत पुलिसियों को दे देता है। यह सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहता है और मंदिर की लागत से कई गुणा अधिक की वसूली हो जाती है।

इसके बाद सिलसिला शुरू होता है पूजा व लंगर चलाने का। इसके लिये भी गाहे-बगाहे वसूली शुरू कर दी जाती है। हरियाणा सरकार वसूली की इस प्रथा के बढते चलन को रोकने के लिये बाकायदा आदेश जारी किया हुआ है। इसी आदेश की अवहेलना करने को लेकर डीजीपी मनोज यादव ने आईजीपी वाई पूरण कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

पंजाबियों का एक और संगठन बना

भाटिया बिरादरी में सामाजिक और राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। भाटिया सेवक समाज के अलावा भाटिया बिरादरी के कई संगठन अभी तक समाजसेवा के नाम पर सक्रिय थे। लेकिन गुरुवार को कुछ और लोगों ने भाटिया एकता मंच को फिर से जिन्दा किया। यह संगठन भाटिया बिरादरी में एकता के नाम पर दोबारा खड़ा किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस बार इसमें कुछ होटल मालिकों को ओहदे दिए गए हैं। ऐसे में यह संगठन होटल वालों का है या भाटिया बिरादरी का है, यह इस संगठन के क्रियाकलापों से तय होगा। राजमंदिर के नाम से होटल चलाने वाले गुलशन भाटिया को अब भाटिया एकता मंच का सरपरस्त और डिलाइट होटल वाले जितेन्द्र भाटिया उर्फ बंटी को इस संगठन वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य बना हुआ है। जब से यह संगठन बना है तब से लेकर आज तक इसके संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम भाटिया ही बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि भाटिया बिरादरी में यह संगठन दो होटल वालों को शामिल करके किनके बीच एकता कराएगा, यह समय के गर्भ में है। फिलहाल इसके कुछ सदस्य इस बात से खुश हैं कि दो होटल वालों को शामिल करने से कम से कम लंच, डिनर का जुगाड़ संस्था की बैठक में हो ही जाएगा।

सस्ती पगड़ी, महंगे किसान नेता

इन दिनों किसान नेताओं की काफी डिमांड है। विशेषकर हरियाणा में तो किसान नेता होना किसी वीआईपी से कम नहीं। सरकारी किसान नेता भी लोग बन रहे हैं। ऐसे में कोई किसान नेता अपने संगठन के नाम में सिर्फ भाकियू (भारतीय किसान यूनियन) लगा ले तो उसके भाव ही बढ़ जाते हैं। हरियाणा में भाकियू चढ़ूनी ग्रुप का ही बोलबाला है। टिकैत वाली भाकियू के नेता राकेश टिकैत भी चढ़ूनी वाली भाकियू के कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन कैथल के फरल गांव के गुणी प्रकाश ठाकुर ने भी भाकियू बना रखी है और वो उसके अध्यक्ष हैं। 2018 तक गुणी प्रकाश भाजपा सरकार का तीखा आलोचक था लेकिन जब सरकार ने उस पर डोरे डालने शुरू किए तो गुणी प्रकाश के सुर बदल गए। दो दिन पहले इसी गुणी प्रकाश को खट्टर से मिलवाने चंडीगढ़ ले जाया गया और वहां ले जाकर उनके नेतृत्व में आए चेले-चाटों की जमकर आवभगत की गई। जब ये लोग सरकारी मेहमाननवाजी से गदगद हो गए तो इन्हें खट्टर के पास ले जाया गया। रास्ते में ही इनके झोले में एक पगड़ी भी डाल दी गई। गुणी प्रकाश पहुंचे और जाते ही उन्होंने बिना देर लगाए वो पगड़ी खट्टर को पहना दी। हालांकि आमतौर पर हरियाणा में किसान उस तरह की रंगीन पगड़ी सिरों पर नहीं बांधते लेकिन मुख्यमंत्री निवास में सब्जी की खुद देखभाल करने वाले खट्टर को भी पता नहीं कि किसान कौन सी पगड़ी पहनते हैं, उन्होंने गुणी प्रकाश की पगड़ी स्वीकार कर ली।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06